POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2020/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

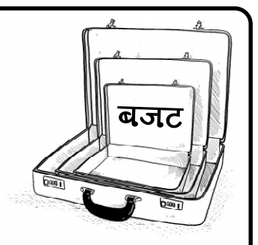

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 अप्रेल, 2020 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट रखा। खासकर, राज्य सरकार इस बार प्रदेश के विकास के लिए बजट में घोषित निम्न सात संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेगी।

1. निरोगी राजस्थान
2. संपन्न किसान
3. महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण
4. सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और जवान
5. शिक्षा का परिधान
6. पानी बिजली व सड़कों का ध्यान
7. कौशल एवं तकनीक प्रधान।

इन संकल्पों के तहत बजट करीब-करीब सभी क्षेत्रों को कवर कर रहा है। रिफाइनरी के काम को तेजी से आगे बढ़ाने, अल्पसंख्यकों को ज्यादा सुविधाएं देने, सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने, स्वरोजगार के लिए युवाओं को कर्ज उपलब्ध कराने, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने, कर्ज वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने और खाद्य वस्तुओं में मिलावट पर सख्त सजा का प्रावधान करने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सभी वर्गों की झोली खुशियों से भरने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व बढ़ाने और बजट घाटे को कम कर वित्तीय अनुशासन अपनाने की बात भी कही है।

मेरा मानना है, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए जाने की जरूरत है, तभी बजट घोषणाएं समय पर क्रियान्वित हो सकेंगी। इसके लिए प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ नौकरशाही को अधिक सक्रिय बनाना आवश्यक है। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रखकर लाभान्वित हो सकें।

1. निरोगी राजस्थान - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहला संकल्प लेते हुए कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। इसे ध्यान में रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट में 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जाएगा।

इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया जाएगा। इसमें से एक-एक करोड़ रुपए हर जिले को अभियान के प्रबंधन, प्रचार-प्रसार, परिचर्चा एवं गोष्ठियां आयोजित करने के लिए मिलेंगे। सभी नागरिकों का डिजिटल हैल्थ सर्वे करने की भी घोषणा की गई है। जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड पर एमआरआई व सीटी स्केन की सुविधा मिल सकेगी।

अगले चार साल में नए बनने वाले सभी 15 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर पांच हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत राशि देगी बाकी हिस्सा राज्य सरकार को खर्च करना होगा। राज्य सरकार जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में कैंसर की जांच के लिए सिटी स्कैन मशीन की व्यवस्था करेगी। जयपुर में कैंसर के उपचार के लिए उच्च श्रेणी का अस्पताल होगा। बजट में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

2. संपन्न किसान - कृषि व किसानों की स्थिति को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए तीन हजार 420 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया है। किसानों की आय में वृद्धि, विपणन व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन, खेती को जोखिम रहित बनाने और किसानों व खरीददार के बीच लाभकारी व्यवस्था बनाने के मकसद से दो नए अधिनियम लाए जा रहे हैं। कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए 25 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिस पर 267 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधीन एक नए डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना की जाएगी।

वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए 12 हजार 500 फार्म पौण्डों का निर्माण कराया जाएगा। दो लाख टन यूरिया और एक लाख टन डीएपी के अग्रिम भण्डारण के लिए 30 करोड़ और ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 91 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य बीज निगम द्वारा प्रमाणित बीज का उत्पादन 8 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 12 लाख क्विंटल किया जाएगा। किसानों की बिजली दर न बढ़े, इसके लिए 14331 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है।

3. महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण

प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 35 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को पोषाहार वितरित किया जाएगा। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और एएनएम के बीच बेहतर समन्वय तथा एक दूसरे से जोड़ने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म 'ए-3 एप' विकसित किया जाएगा।

साथ ही उनके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 8 हजार 500 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा की है। करीब 4 लाख 22 हजार से अधिक बच्चे पालनहार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिस पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

बाल अधिकार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए 100 करोड़ रुपए से नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन किया जाएगा। जिसके तहत बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसे कामों पर रोक लगाई जाएगी। अजमेर के मसूदा और भरतपुर जिले के कामां ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से अल्पसंख्यक बालक-बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान वक्फ बोर्ड को सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

4. सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और जवान

बजट में फिट राजस्थान, हिट राजस्थान का लक्ष्य रखते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें आगे लाने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। इससे राज्य खेल ज्यादा सफल हो सकेंगे। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जाएगा।

प्रदेश के खिलाड़ियों की ओर से ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए एवं कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। पहले यह राशि क्रमशः 75 लाख, 50 लाख व 30 लाख रुपए थी। इसी तरह एशियन/कॉमनवेल्थ गेम्स एवं खिलाड़ियों के दैनिक भत्तों में भी वृद्धि की गई है। प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना व औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाएगा।

राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीको द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से खादी प्लाजा की स्थापना होगी। राज्य में नई 57 पंचायत समितियों व 1456 नई ग्राम पंचायतों में भवनों का निर्माण कराया जाएगा। मनरेगा को मजबूत बनाने के लिए काम मांगो अभियान के तहत मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

5. शिक्षा का परिधान

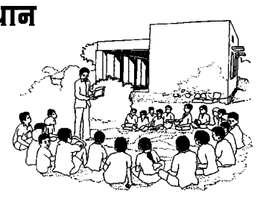

शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए बजट में कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त संकाय और 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त विषय जरूरत के मुताबिक खोले जाएंगे। बालिका शिक्षा के लिए 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और राज्य के 167 ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय होंगे। इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे रहेगा। इस दिन छात्र-छात्राओं को स्कूल में बस्ता लेकर नहीं जाना होगा। कोई अध्यापन कार्य भी नहीं होगा। इस दिन परिजन और अध्यापक मीटिंग करेंगे। साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हैप्पीनेस थैरेपी, खेलकूद, व्यक्तिगत विकास और नैतिक शिक्षा बाल सभाएं होंगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए नए कंप्यूटर शिक्षक का कैडर सृजित किया जाएगा।

महाविद्यालयों में पढ़ रहे युवाओं के लिए स्किल बढ़ाने और ट्रैनिंग कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। इसमें राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर साल 10 हजार विद्यार्थियों को ट्रैनिंग दी जाएगी।

6. पानी बिजली व सड़कों का ध्यान

बजट में पेयजल के लिए 8794 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। पूरे प्रदेश में शहरों की तर्ज पर ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 16 जिलों की 30 परियोजनाओं के काम शुरू होंगे। इसमें 4 हजार 327 गांवों एवं 9 हजार 159 ढाणियों के लगभग 9 लाख परिवारों को फायदा होगा।

इस काम में 1 हजार 350 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। नल से हर घर में पेयजल आपूर्ति के लिए 625 करोड़ की लागत से काम कराए जाएंगे। शहरों में पेयजल की पुरानी लाइनों को बदला जाएगा। इस पर 165 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में 4557 करोड़ रुपए का प्रावधान जल संसाधन के लिए है। नदियों-बांधों की 'पाल' बांधने के काम होंगे।

ऊर्जा विभाग के लिए 18 हजार 530 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान बजट में है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत 30 हजार मेगावाट तक उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके लिए अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति सहित कुल 50 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। सभी जिलों में खेती के लिए दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में 400 करोड़ रुपए से सड़कों का जीर्णोद्धार होगा। ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा।

4245 करोड़ रुपए से पीएमजीएसवाई के तहत 8663 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़क हादसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। सड़क दुर्घटना में घायल का इलाज करना अब नजदीकी निजी अस्पताल के लिए बाध्यकारी होगा।

7. कौशल एवं तकनीक प्रधान

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम राज्य को स्किल और आईटी के तालमेल से फिजीकल से डिजिटल इको सिस्टम की ओर ले जाएंगे। प्रदेश के सभी 229 राजकीय आईटीआई में ई-क्लास रूम के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष की घोषणा की है।

स्टार्टअप के विकास के लिए 75 हजार करोड़ रुपए के राजीव गांधी फंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं सहित अन्य संस्थानों में स्थापित इन्क्यूबेटर्स को आई स्टार्ट राजस्थान से जोड़ा जाएगा। राजीव गांधी सेवा केंद्रों को 'राजीव गांधी ग्रामीण आइटी हब' राजगृह के रूप में विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं की अदायगी की जाएगी।

भामाशाह की जगह राजस्थान जन आधार योजना आरम्भ की जा चुकी है। नागरिक सुरक्षा और एसडीआरएफ की क्षमता बढ़ाने के लिए 10-10 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। गांवों में कृषि उत्पाद प्रोसेसिंग इकाइयां लगेंगी। इससे किसानों को फायदा होगा।

कोराना वायरस संक्रमण से बचने और फैलने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते है:

- अपने हाथों को साबुन और पानी से बार-बार धोते रहें।
- सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।

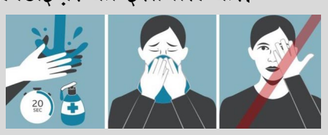

- खांसते और छींकते वक्त टीशू का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए टीशू को फेंक दें।
- बीमार व्यक्ति के नज़दीक जाने से बचें।
- बिना हाथ धोए अपनी आंख, नाक या मुंह को न छुंए।

बिजली मित्र एप्प और ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान के अन्य तरीके

मोबाइल एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से, बिजली मामलों में उपभोक्ताओं की सहूलियत को बढ़ाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने 'बिजली मित्र' एप्प विकसित किया है। उपभोक्ता इस एप्प के माध्यम से बिल का विवरण, बिल भुगतान, शिकायत पंजीकरण और खपत का आंकलन इत्यादि कर सकते हैं। इस एप्प को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर एक वेबसाइट द्वारा भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह उपभोक्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम और जोधपुर विद्युत वितरण निगम के लिए WSS पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। ये पोर्टल हालांकि अभी तक सिर्फ एक वेबपेज के माध्यम से उपलब्ध है। बिजली मित्र और WSS पोर्टल का वेब एड्रेस नीचे दिया जा रहा है:

JVVNL बिजली मित्र: https://www.bijlimitra.com/custumerLoginPage
AVVNL WSS पोर्टल: http://wss.rajdiscoms.com/avvnl_web/
JdVVNL WSS पोर्टल: http://jai-wss-ap.rajdiscoms.com/jdvvnl_web/

इन एप्स और अन्य सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से, उपभोक्ता बिल के देर से पहुंचने के वजह से विलम्बित भुगतान की समस्या का निपटारा और ई-मित्र, बिजली कार्यालय आदि पर बिल जमा कराने के लिए जो समय लगता है उसकी बचत कर सकते हैं। उपभोक्ता बिजली बिल भुगतान के लिए अन्य एप्स जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कद्दूस' जयपुर